



जयपुर में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद वकील आरोपियों को देखकर आक्रोशित हो गए और पुलिस की मौजूदगी में ही उनसे मारपीट कर दी। वकीलों ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर बेरोजगारी का हक मारने की बात कही। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया और बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट परिसर में वकीलों ने पेपरलीक आरोपियों को पीटा

पेपरलीक की जांच कर रहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) ने गिरफ्तार किए सभी 14 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया

जयपुर, 6 मार्च। सब इन्स्पेक्टर (एस.आई.) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते समय वकीलों ने पीट दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपियों का बीच बचाव करते हुए उन्होंने कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें 12 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

एस.ओ.जी. (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने पेपर लीक मामले में बुधवार को गिरफ्तार 14 ट्रेनी एस.आई. नरेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, करणपाल गोदारा, विवेक भांडू, मनोहर लाल, गोपीराम, श्रवण कुमार, रोहितारव कुमार, प्रेम सुधी, एकता, भगवती, राजेश्वर, नारंगी और चंचल कुमारी को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर, द्वितीय के समक्ष पेश किया। अदालत में पेशी के लिए ले जाते समय आरोपियों को देखकर वकील भड़क गए और उन्होंने आरोपियों से मारपीट

- आरोपियों को देखकर वकील भड़क गए और आरोपियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस को आरोपियों को आक्रोशित वकीलों से बचा कर जज के सामने ले जाने के लिए भारी मशकत करनी पड़ी।
- अदालत ने हालांकि आरोपियों को 12 मार्च तक रिमांड दे दे दिया, पर एस.ओ.जी. से यह भी पूछा कि, आरोपियों को अवैध हिरासत में क्यों रखा और धारा 41 ए के प्रावधानों का पालन क्यों नहीं किया गया।

की। जब पुलिस ने बीच-बचाव किया तो वकील पुलिस से भी भिड़ गए कुछ ही देर में कोर्ट परिसर छानवी में तब्दील हो गया और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। वकीलों ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर बेरोजगारी का हक मारने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान एक महिला आरोपी के परिवारजन तीन माह की बच्ची के साथ अदालत में हाजिर हुए उन्होंने कहा कि आरोपी महिला को तीन माह

की बच्ची है। ऐसे में उसे रिमांड पर नहीं भेजा जाए। इससे पहले एस.ओ.जी. ने सुरक्षा के बीच आरोपियों को अदालत में पेश कर उनका पुलिस रिमांड भंगा। इसका विरोध करते हुए आरोपियों के अधिवक्ता विपुल शर्मा और वेदांत शर्मा सहित अन्य ने कहा कि एस.ओ.जी. इस प्रकरण में मनमानी कर रही है। आरोपियों को तीन और चार माह को पकड़ा, लेकिन 24 घंटे

के भीतर अदालत में पेश नहीं किया। इसके अलावा प्रकरण सात साल से कम सजा से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में तय कर रखा है कि ऐसे मामलों में सी.आर.पी.सी. की धारा 41 ए के तहत पुलिस गिरफ्तारी से पूर्व नोटिस देनी या उसे तत्काल गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। इस मामले में एसओजी ने इसकी अवहेलना की है। इस पर अदालत ने मामले में एस.ओ.जी. से 12 मार्च तक स्पष्टीकरण मांगा है कि आरोपियों को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि प्रकरण में सी.आर.पी.सी. की धारा 41 ए के प्रावधानों की पालना क्यों नहीं की गई। हालांकि अदालत ने आरोपियों को 12 मार्च तक पुलिस अधिभक्ष में भेज दिया।

सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने में साधु संतों की महती भूमिका- मुख्यमंत्री भजन लाल

गोपाल क्रेडिट कार्ड से पशुपालकों को 1 लाख रु. का ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है

- साधु-संतों ने ई.आर.सी.पी. तथा यमुना जल समझौते के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
- मु.मंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि, राज्य सरकार ने ढाई माह के कार्यकाल में प्रदेश में पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया है। पूर्वी राजस्थान के लिए ई.आर.सी.पी. तथा शेखावाटी के लिए ताजेवाला हैडवर्क्स परियोजना की सौगात दी गई है।



मु.मंत्री भजनलाल शर्मा ने गौ भक्त एवं संत समाज की सभा को वरुंडल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) तौर पर संबोधित किया। दरअसल, मु.मंत्री भजनलाल कोरोना पॉजिटिव हो गये हैं, तथा कोरोना क्वारंटीन के नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अपने ओ.टी.एस. स्थित आवास से प्रशासनिक एवं सार्वजनिक कार्यों को निपटा रहे हैं।

जयपुर, 6 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि, संत-महात्माओं के आदर्श जीवन से प्रेरणा पाकर हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है और सनातन धर्म, संस्कृति को बढ़ावा देने में संतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है तथा पशुधन के कल्याण हेतु राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा पशुपालकों को लाभांशित कर रही है। भजनलाल शर्मा ने ओ.टी.एस. स्थित मुख्यमंत्री निवास से बुधवार को संत समाज-गौभक्तों की आभार सभा को वरुंडल माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में आए साधु-संतों ने गौमाता

के हितों के लिए किए गए निर्णयों, ई.आर.सी.पी. तथा यमुना जल समझौते के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने ढाई माह के अल्प कार्यकाल में पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया है। पूर्वी राजस्थान के लिए ई.आर.सी.पी. परियोजना तथा शेखावाटी क्षेत्र के लिए ताजेवाला हैडवर्क्स के ऐतिहासिक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर, साथ ही, उदयपुर में देवास बांध परियोजना तृतीय एवं चतुर्थ के माध्यम से दक्षिण राजस्थान में भी जल

की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने गौवंश संरक्षण के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की है जिसके तहत पशुपालकों को 1 लाख रूपय तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार ने पशुधन के लिए मोबाइल वैटरनरी यूनिट की भी शुरुआत की है। इन यूनिट्स के माध्यम से पशुओं को समय पर चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कार्यक्रम में बुधगिरी मढ़ी (फतेहपुर शेखावाटी) के पीठाधीश्वर एवं गोसेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश गिरी महाराज ने राज्य सरकार का

धन्यवाद देते हुए कहा कि सनातन धर्म संस्कृति तथा गोसेवा संरक्षण के लिए राज्य सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच तथा उनके नेतृत्व के कारण यह संभव हो सका है। समारोह में गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद सी.पी. जोशी, सुमेधानंद सरस्वती, विधायक बालमुकुन्दचार्म, रेवासा धाम पीठाधीश्वर राधवाचार्य महाराज, संत गोविंद वल्लभ महाराज, रघुनाथ भारती सहित बड़ी संख्या में साधु-संत उपस्थित थे।

राहुल गांधी को भाषणों में "सतर्कता" बरतने की सलाह दी चुनाव आयोग ने

नई दिल्ली, 6 मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने सार्वजनिक बयानों में सतर्क रहने की सलाह जारी की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले चुनाव आयोग से कहा था कि, वह पिछले साल नवंबर में अपने भाषण के लिए कांग्रेस सांसद के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं पर हमला करते हुए "जेबकत" शब्द का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी पर "पनौती" और जेबकत वाले तंज को लेकर राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था।

- चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नया नोटिस जारी किया है कि, जिसमें चुनाव प्रचारों के दौरान संयमित और मर्यादित भाषा का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
- दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गत वर्ष फैसला सुनाते हुये चुनाव आयोग को राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
- चुनाव आयोग ने वही नोटिस दोबारा राहुल गांधी को जारी किया है। चुनाव आयोग ऐसा ही एक नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ पहले भी जारी कर चुका है।

गांधी के जवाब सहित प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियों से संबंधित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, भारत के चुनाव आयोग ने सलाह दी है कांग्रेस नेता भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहें।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सार्वजनिक बयान देते समय सभी दलों, स्टाफ प्रचारकों और उम्मीदवारों को आयोग की सलाह का ध्यान रखने को कहा है। चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा और अत्यधिक संयम बनाए रखने और चुनाव प्रचार के स्तर को बढ़ाने के लिए एक सलाह जारी की

थी। सुत्रों ने कहा कि, चुनाव आयोग आगामी चुनावों में समय और सामग्री के संदर्भ में दिए जाने वाले नोटिस पर फिर से काम करने के लिए उचित आधार के रूप में सलाह के अनुसार किसी भी अपर्याप्त एमपीसी उल्लंघन का आकलन करेगा। बता दें कि, जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखें का ऐलान होने वाला है। माना जा रहा है अप्रैल और मई में देशभर में वोट डाले जाएंगे। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का विपक्ष के गठबंधन वाले इंडिया अलायंस से होगा।

23 करोड़ किसानों ने फसल बीमा दावों का लाभ लिया

नई दिल्ली 6 मार्च (वार्ता)। पिछले आठ वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 56 करोड़ 80 लाख किसानों के आवेदन पंजीकृत किए गए और 23 करोड़ 22 लाख से अधिक किसानों को उनके दावों का भुगतान किया गया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि, इस दौरान किसानों ने प्रीमियम के इतिहास से रूप में लगभग 31 हजार 139 करोड़ रुपये चुकता किया, जिसके आधार पर उन्हें 1,55,977 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान दावे के रूप में किया गया। इस प्रकार, किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए एक उल्लेख 500 रुपये दावे के रूप में दिये गये।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आधुनिकीकरण है और यह राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान किसान आवेदनों की संख्या में साल-दर-साल क्रमशः 33.4 प्रतिशत और 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान, अब तक योजना के तहत नामांकित किसानों की संख्या में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बैंगलुरु शहर में चौंकाने वाली सूखे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नहीं है। अब तक यहाँ के निवासियों के लिए यह कठिन स्थिति है। कई लोग पानी की सप्लाई को लेकर ऐसे प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं कि कई रोजिडैन्सियल गेटेड कम्युनिटीज ने पानी की राशनिंग शुरू कर दी है और कार धोने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए हैं। हाइड्रोजन कॉम्प्लैक्स के भीतर पानी के उपयोग को सीमित किया जा रहा है। पानी की सप्लाई को नियमित करने के लिए राज्य सरकार भी इरकत में आ गई है। उसने प्राइवेट टैंकर्स को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कर्नाटक के यातायात विभाग ने सोमवार और मंगलवार को आर.टी.ओ. को निर्देश दिए कि वह प्राइवेट टैंकर्स को जब्त कर आवासीय कॉलोनी को नियमित करे। अन्य आवश्यक जरूरतों की आपूर्ति को नियमित करने के लिए करें। बैंगलुरु वॉटर सप्लाई एण्ड सीवरेज बोर्ड (बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी.) को घर-घर पानी सप्लाई करवाने में मदद देने के लिए आर.टी.ओ. ने दो दिनों में 163 टैंकर जब्त किए। शहर के 16 आर.टी.ओ.ज में से प्रत्येक ने 210 से 15 वाटर टैंकर जब्त कर शहर की आवासीय कॉलोनीयों में जल आपूर्ति में मदद की।

सरकार प्राइवेट टैंकर्स को नियंत्रित करने व उनके द्वारा वसूली जाने वाली कोमत को नियमित करने की प्रक्रिया में है। राज्य के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पानी के टैंकर्स के मालिकों को पहले ही चेतावनी दे दी है कि यदि उन्होंने 7 मार्च तक आर.टी.ओ. में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।

राज्य सरकार को हस्तक्षेप कर कठोर कदम उठाने पड़े क्योंकि मानसून के दौरान हुई कम बारिश के कारण कई आवासीय कॉलोनीयों में पानी की किल्लत की खबरें थीं और पानी की भारी मांग को देखते हुए प्राइवेट वॉटर टैंकर मंगवाना भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। साउथ बैंगलुरु स्थित एक आवासीय कॉलोनी के एक पदाधिकारी ने बताया कि शहर में आवासीय प्रॉपर्टीज में हुई बेशुमार वृद्धि और पानी की मांग में तेजी से वृद्धि के कारण ऐसी स्थिति बनी, और अल्प वर्षा ने समस्या बढ़ा दी।

चुंकि लगजरी गेटेड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स प्राइवेट वॉटर टैंकर्स पर निर्भर थे, इसलिए वे विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं क्योंकि अब जल बोर्ड

ने पानी के वितरण को सीमित कर दिया है। शहर की पॉश कनकपुरा रोड स्थित एक प्रतिष्ठित अपार्टमेंट ने अपने निवासियों को सलाह दी है कि वह डिस्पोजेबल प्लेट्स व वैट वाइप्स का इस्तेमाल कर पानी की बचत करें।

एक अन्य हाई राइज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ने अपने निवासियों के लिए पानी के उपयोग को सीमित कर उसकी राशनिंग कर दी है और किसी भी निवासी को कार आदि धोते हुए पाए जाने पर उस पर 5 सौ रूपए जुर्माने का प्रावधान भी किया है। इस कॉम्प्लेक्स के सिन्डिकेटी गार्ड्स से भी कहा गया है कि वे निवासियों की पालना ना करने वाले लोगों को चिन्हित करें।

संयोगवश, रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को सूचित किया है कि आर.टी.ओ. और बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. प्राधिकरण वॉटर टैंकर्स जब्त कर रहे हैं जिसे जलापूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। पानी उन क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा है, जहां इसकी जबरदस्त किल्लत है। कई बोवेल भी सूख गए हैं, जिसका मतलब है कि शहरवासियों को मानसून का इंतजार करना पड़ेगा, जो अभी तीन महीने दूर है।

कांग्रेस भी जल्द जारी करेगी लिस्ट, सौ उम्मीदवारों के नाम सामने आयेगे

नई दिल्ली, 6 मार्च। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 195 नाम हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी आम चुनाव के लिए जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसके लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बृहस्पतिवार को बैठक होगी जिसमें 100 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी कि, सेंट्रल इलैक्शन कमेटी (सी.ई.सी.) की बैठक सात मार्च को शाम छह बजे होगी।

इस बीच मॉडिया रिपोर्ट्स हैं कि, प्रियंका गांधी वाड़ा यूपी की रायबरेली से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। उधर, राहुल गांधी अमेठी समेत दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं।

कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने वाली कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक 7 मार्च को शाम 6 बजे होगी।" सीईसी की बैठक में विभिन्न स्क्रॉनिंग कमेटी द्वारा भेजे नामों में से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई

डॉनल्ड ट्रम्प का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना तय हुआ

वाशिंगटन, 6 मार्च (वार्ता)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प अस्तित्वा से जीत की ओर अग्रसर होने के साथ ही आगामी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गये हैं।

एनबीसी-न्यूज ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनबीसी न्यूज के मुताबिक ट्रम्प को 9,200 से

अधिक यानी 87.6 प्रतिशत वोट मिले हैं, जबकि उनकी इकलौती प्रतिद्वंद्वी निवकी हेली को केवल 12 प्रतिशत वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत हेली सभी राज्यों में ट्रम्प से हारती दिख रही हैं। ट्रम्प ने मंगलवार को 15 रिपब्लिकन प्राइमरी में से 13 में जीत हासिल कर ली है जबकि यूटा राज्य के परिणाम अब भी शेष हैं।

वर्षों बाद चैन की नींद सोएंगी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) संदेशखाली स्थित शाहजहां के घर पहुंची थी। राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री फिलहाल ई.डी. की हिरासत में हैं जहाँ सरकार की राशन वितरण स्कीम डे फण्ड्स में हेराफेरी को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।

लेकिन, इस दौरान जो तथ्य सामने आए, उनके सामन पूर्व की सभी जांच पड़ताल बौनी साबित होने लगी। संदेशखाली के एस.सी. व एस.टी. लोगों के साथ शाहजहां और उसके सहअपराधियों द्वारा किए गए कुकृत्यों का भण्डा फोड़ हुआ। यह पता चला कि शाहजहां और तृणमूल कांग्रेस के उसके सहअपराधी यहाँ वर्षों से अपनी अवैध गतिविधियाँ चला रहे थे।

तृणमूल के नेता स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जे कर रहे थे, उनसे घन एंठ रहे थे और यह भी सामने आया कि स्थानीय महिलाओं से एक सुनिश्चित तरीके से बलात्कार किए जा रहे थे।

स्थानीय महिलाओं के आंदोलन के कारण ही ये अपराध नजर में आए महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आयां और उन्होंने तृणमूल के गुण्डों को तुरन्त प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की। इनके विरोध प्रदर्शन करने की मांग की। इनके विरोध प्रदर्शन पर ना केवल बंगाल बल्कि पूरे देश की नजर गई।

विरोध, जैसे-जैसे तीव्र होता गया, आरोपियों की सम्पत्तियों में आग लगाई जाने लगी। ऐसा लगा जैसे कि तृणमूल

के गुण्डों की घमकियां व भय भी इस भाग की भेद चढ़ गए। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण ही प्रशासन का हकत में आकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा।

शाहजहां को सी.बी.आई. के सुपुर्द करने के साथ ही क्षेत्र की महिलाओं को राहत की सांस मिली है, लेकिन उन्हें आशंका है कि इस मामले में यदि सरकार का दखल नहीं रहा तो राज्य सरकार शाहजहां को छोड़ देती और उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती।

प्रधानमंत्री ने भी संदेशखाली के एक निकटवर्ती क्षेत्र का दौरा किया था। उनका इन यह मानना था कि तृणमूल कांग्रेस ने इन तत्वों को प्रोत्साहित कर भारी पाप किया है।

अलवर में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) निर्णय लिया गया। बैठक में ई.एस.आई.सी. के सात अस्पतालों का निर्माण करने को मंजूरी दी गई। ये अस्पताल उत्तर प्रदेश के मेरठ और बरेली में, मध्य प्रदेश के पीथमपुर, कर्नाटक के हरोहल्ली, नरसापुरा व गोवा में निर्माण में हैं, जिनके निर्माण की लागत 1128.21 करोड़ रु. आयागी। इन अस्पतालों के निर्माण के बाद ई.एस.आई.सी. की मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं में 800 बिस्तरों की बुनियादी तौर पर वृद्धि हो जाएगी।